● वर्ष : 04 ● अंक : 258

● गाजियाबाद, शुक्रवार 06 फरवरी 2026

● पृष्ठ-6 ● मूल्य : दो रूपये

● RNI No - UPHIN/2022/84480

E-mail: swastiksaharanews@gmail.com

www.swastiksahara.com

दूसरे मनुष्यों की सेवा करना, लाखों जप तप के बराबर है।

नई दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी, बोले-

'देश सुधार एक्सप्रेस पर सवार, अब हमें रुकना नहीं है'

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्थगित किए जाने के एक दिन बाद, गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना शुरू किया। विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री के अभिभाषण शुरू होते ही कई विपक्षी नेताओं ने 'एलओपी को बोलने दो' और 'तनशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर कटाक्ष करते हुए, पीएम मोदी ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खरगे जी की उम्र को देखते हुए, मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि उन्हें बैठकर नारे लगाने की अनुमति दें ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। पीछे युवा लोग बैठे हैं। इसलिए, कृपया खरगे जी को बैठे-बैठे भी नारे लगाने की अनुमति दें। मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में, बीते वर्ष देश के तीव्र विकास के वर्ष रहे हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में बदलाव का युग रहा है। देश सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई भाग पूरा हो चुका है। लेकिन यह दूसरा चौथाई भाग उतना ही निर्णायक है जितना पिछली सदी में

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चौथाई भाग था। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में यह दूसरा चौथाई भाग भी उतना ही सक्षम साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने इस देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, गांव, किसान, महिलाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि... सभी विषयों को विस्तार से रखते हुए भारत की प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजाया है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है।

इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। ये हम सभी के लिए प्रेरक है। आज राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि हम एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब हमें न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है। हमें तेज गति से चलना है और लक्ष्य प्राप्त करके ही आगे बढ़ना है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पर पड़ाव पर पहुंची है, हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसी समय दिनोंदिन हमारा देश युवा होता जा रहा है। युवा आबादी वाला देश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत के प्रति विश्व का आकर्षण बढ़ा है, उसमें भी विश्व, भारत के टैलेंट का माहत्म्य समझ रहा है। आज हमारे पास दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण युवा टैलेंट पुल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है और सामर्थ्य भी है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला देश बना हुआ है।

सस्ता सफर और जीरो कमीशन: अमित शाह ने लॉन्च की भारत टैक्सी, सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह एक सहकारी स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवरों को मालिक की तरह काम करने की सुविधा देता है, जिससे कमीशन शून्य हो जाता है और कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी (सर्ज प्राइसिंग) समाप्त हो जाती है। इस सेवा का उद्देश्य उबर और ओला जैसे ऐप्स को टक्कर देना है। सहकारिता मंत्रालय ने भारत टैक्सी को परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बताया है, जो ड्राइवरों (जिन्हें सारथी कहा जाता है) को स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखती है, जिससे वे शोषणकारी एग्रीगेटर-आधारित मॉडलों से मुक्त हो जाते हैं।

लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सेवा टैक्सी चालकों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करेगी और उन्होंने कहा कि टैक्सी क्षेत्र में औपचारिक रूप से सरकार नहीं, बल्कि सहकार प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली में प्रत्येक सारथी चालक टैक्सी का मालिक होगा और यह ढांचा एक क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन लाएगा। गुजरात के अमूल की तरह, यह विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा सहकारी मॉडल है। आपकी टैक्सी के पहिए सारथी समुदाय के लाभ के लिए चलेंगे - यही सहकारिता की भावना है।

शाह ने आगे बताया कि भारत टैक्सी की परिकल्पना एक एकीकृत परिवहन मंच के रूप में की गई है जो दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी 'सारथी दीदी' महिला यात्रियों और चालकों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि टैक्सी सेवा तीन वर्षों में शुरू हो जाएगी और सरकार प्लेटफॉर्म द्वारा अर्जित राजस्व का 20% हिस्सा लेगी, जबकि शेष राशि प्रत्येक सारथी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

यूरोपीय और अमेरिका के बाद अब खाड़ी देश भारत से व्यापार समझौता करने को तैयार

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में तेजी दिखाने के बाद अब खाड़ी देश भी भारत के साथ हाथ मिलाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की बढ़ती साख, आत्मविश्वासी विदेश नीति और मजबूत होती आर्थिक ताकत की साफ गूंज है।

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को बाजार भर नहीं, बल्कि साझेदार शक्ति के रूप में देखने लगी हैं। हम आपको बता दें कि भारत और खाड़ी क्षेत्र के छह देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम उठने जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में दोनों पक्ष वार्ता की रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह रूपरेखा आने वाली बातचीत का दायरा, तरीका और प्राथमिकताएं तय करेगी। इस तरह लगभग दो दशक से अटकी प्रक्रिया अब फिर गति पकड़ती दिख रही है। खाड़ी सहयोग परिषद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। भारत पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू कर चुका है और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऐसे में अब पूरे समूह के साथ व्यापक समझौता भारत की व्यापार नीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार का आधार अभी तक ऊर्जा रहा है। भारत अपने कच्चे तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से मंगाता है। सऊदी अरब और कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं। दूसरी ओर भारत इन देशों को मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, धातु, कृत्रिम आभूषण, बिजली उपकरण, लोहा, इस्पात और रसायन भेजता है। आंकड़े बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है।

हाल के वर्ष में भारत का निर्यात लगभग 57 अरब डॉलर के आसपास रहा, जबकि आयात 121 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। कुल द्विपक्षीय व्यापार 178 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। यह स्तर अपने आप में इस संबंध की गहराई बताता है। खाड़ी देश भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए भी बड़ा केंद्र हैं। लगभग तीन करोड़ से अधिक भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उनमें से बड़ी संख्या इसी क्षेत्र में काम करती है। वह हर वर्ष भारी धनराशि भारत भेजते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण सहारा है। पहले भी भारत और इस समूह के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी थी, पर 2008 के बाद प्रक्रिया रुक गई।

तरबूज या 'चलता-फिरता बम'? केरल पुलिस ने पकड़ा बारूद से लदा ट्रक, कोयंबटूर से त्रिशूर तक फैला तस्करी का जाल!

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

केरल। केरल के पलक्कड़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की खेप बरामद की है। पलक्कड़ मेडिकल कॉलेज के पास एक पिकअप वैन से 100 से अधिक जिलेटिन स्टिक के डिब्बे और 20 से ज्यादा डेटोनेटर के डिब्बे जब्त किए गए हैं। विस्फोटक ले जाने का तरीका इतना शातिराना था कि पुलिस भी दंग रह गई।

तरबूजों के नीचे छिपा था 'मौत का सामान'

पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, यह जब्ती बुधवार देर रात की गई। खुफिया जानकारी मिली थी कि राज्य में विस्फोटकों की एक बड़ी खेप लाई

जा रही है। इसी आधार पर जब पुलिस ने एक पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा कर वैन को घेरा और तलाशी ली।

गाड़ी का ड्राइवर हिरासत में

पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान सेंथिल के रूप में हुई है। शुरूआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने कोयंबटूर से डिब्बे लोड किए थे और उन्हें त्रिशूर में एक खदान में ले जा रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले ही राज्य में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वाहनों की चेकिंग के दौरान पिकअप वैन को रोका गया। हालांकि, ड्राइवर ने कहने पर भी गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। अब ड्राइवर के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

विस्फोटक का इस्तेमाल खदान के कामों में किया जाना था

शुरूआती जांच से पता चलता है कि विस्फोटक को काले पत्थर की खदान के कामों में इस्तेमाल के लिए गुप्त रूप से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल विस्तृत जांच चल रही है।

चुनाव आयोग का सख्त रुख: पश्चिम बंगाल सरकार को 'अल्टीमेटम', 9 फरवरी तक अनुपालन के निर्देश

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनाव संबंधी निदेशों की कथित अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने एक कड़ा पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार को आगाह किया है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण निदेशों का पालन नहीं किया गया है। अब आयोग ने राज्य सरकार को इन निदेशों के समयबद्ध अनुपालन (Time-bound Compliance) के लिए 9 फरवरी 2026 तक की अंतिम समय सीमा दी है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद पहले जारी किए गए कई निदेशों का पालन नहीं किया गया है। आयोग ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), दो सहायक ईआरओ (एईआरओ) और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में आयोग ने पांच अगस्त 2025 और दो जनवरी 2026 को भेजे गए अपने पत्रों का भी उल्लेख किया। आयोग ने यह भी कहा कि बशीरहाट-2 की एईआरओ और प्रखंड विकास अधिकारी सुमित्रा प्रतिम प्रधान को निलंबित नहीं किया गया है, जबकि उन पर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से 11 अतिरिक्त एईआरओ की अनधिकृत तैनाती का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 25 जनवरी 2026 के पत्र के जरिए 48 घंटे में अनुपालन करने के लिए कहा गया था। यह 21 सितंबर 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा 31 मई 2023 को जारी आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है।

इसके अलावा आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 27 अक्टूबर 2025 को जारी उसके निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद तीन मतदाता सूची पर्यवेक्षकों अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे के तबादले अब तक रद्द नहीं किए गए हैं। इस संबंध में 27 जनवरी 2026 को भेजे गए पत्र में 28 जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था। आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी चिंता जताई और कहा कि ये उसके निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप

निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह देरी न केवल आयोग के दिशा-निदेशों का, बल्कि 21 सितंबर 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 25 जनवरी को दिए गए '48 घंटे के अल्टीमेटम' को भी राज्य प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया।

नियुक्तियों के मानकों पर सवाल

कार्रवाई के अलावा, आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी आपत्ति जताई है। ईसी का कहना है कि ये नियुक्तियां आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।

उन्नाव में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

उन्नाव (स्वास्तिक सहारा)। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस भीषण एक्सीडेंट में एक दंपति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा एक ट्रक चालक की लापरवाही और भागने की कोशिश के कारण हुआ। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, यह हादसा बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे सोहरामऊ थाना क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भल्ला फार्म के पास हुआ। हसनगंज क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि लखनऊ से कानपुर जा रहे एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश में गति बढ़ा दी, जिसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इस दोपहिया वाहन पर सवार दंपति और उनके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कुमार ने बताया कि यह परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था। मृतकों की पहचान उन्नाव जिले के अजगैन गांव के निवासी वीरेंद्र (35), उनकी पत्नी रितु (33), उनकी नौ वर्षीय बेटी और छह वर्षीय बेटे के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर देर रात ट्रकों की अनियंत्रित गति और ओवरटेकिंग की समस्या पहले भी कई जानलेवा हादसों का कारण बन चुकी है।

उधमपुर मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर ढेर, दो पाकिस्तानी आतंकी मारे गए

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर रुबानी उर्फ अबु माविया भी शामिल है। यह ऑपरेशन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया। मुठभेड़ करीब 20 मिनट तक चली। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान और कड़ी निगरानी जारी है।

रूस से तेल खरीद, अमेरिकी टैरिफ, व्यापार समझौते, यूएस-ईरान वार्ता संबंधी सवालों के एमईए ने दिये जवाब

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत ने आज कहा कि अपने 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी शीर्ष प्राथमिकता है और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद को लेकर उसका नजरिया मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेसवार्ता में ये टिप्पणियां अमेरिका के इस दावे के जवाब में कीं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। जायसवाल ने कहा, ''जहां तक भारत की ऊर्जा खरीद का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।'' उन्होंने कहा, ''बाजार की स्थितियों और बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाना, हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी कदम इसी बात को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं और भविष्य में भी इसका अनुसरण किया जाएगा।"

जायसवाल ने यह भी रेखांकित किया कि ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भारत की स्थायी नीति है। यानी भारत एक ही देश पर निर्भर रहने की बजाय कई विकल्प खुला रखता है ताकि

आपूर्ति, कीमत और रणनीतिक संतुलन बना रहे। यह बयान अपने आप में उन सभी अटकलों पर प्रहार था जो यह दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि भारत किसी एक खेमे की तरफ झुक रहा है।

वेनेजुएला को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इतिहास और वर्तमान दोनों सामने रखे। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला लंबे समय से भारत का ऊर्जा साझेदार रहा है। वर्ष 2019 तक वहां से तेल आता रहा, लेकिन प्रतिबंधों के कारण खरीद रोकनी पड़ी। बाद में 2023 और 2024 के बीच कुछ समय के लिए खरीद फिर शुरू हुई, पर दोबारा प्रतिबंध लगने से उसे रोकना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उपक्रम वहां काम कर रही अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ साझेदारी रखे हुए हैं और यदि वाणिज्यिक लाभ दिखा तो भविष्य में आपूर्ति पर विचार होगा।

जायसवाल ने साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच दूरभाष पर वार्ता के बाद जो स्थिति बनी, उसके आधार पर परस्पर शुल्क में कमी को लेकर अमेरिका ने कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अब भारत में बने उत्पाद अमेरिका को 18 प्रतिशत शुल्क पर भेजे जा सकेंगे। इसे उन्होंने भारतीय निर्यात के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से भी यही शुल्क दर स्पष्ट की गई है। जायसवाल ने साथ ही एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि ईरान में पकड़े गए 16 भारतीय नाविकों को वाणिज्य दूतावासीय की पहुंच मिल चुकी है। बंदर अब्बास में भारतीय अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है।

नगर आयुक्त ने की निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

227 करोड़ के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने के दिये निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा शहर के विकास कार्यों को रफ्तार दी जा रही है इंदिरापुरम सहित प्रत्येक वार्ड में निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए कार्यों को धरातल पर कराया जा रहा है आंतरिक वार्डों में इंटरलॉकिंग टाइल, नालिया, पुलिया बनाने के साथ-साथ मुख्य प्रमुख मार्गो के सड़क सुधार का कार्य भी निरंतर जारी है जिसमें नालों के निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं, नगर आयुक्त द्वारा लगातार चल रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है इसी क्रम में समस्त निर्माण विभाग टीम के साथ नए कार्यों को करने के लिए भी समीक्षा की गई जिसमें विकास की श्रंखला में 227 करोड़ के कार्यों को प्रारंभ करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, मौके पर मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी तथा सभी जोन के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर व अन्य टीम भी उपस्थित रही। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया अवस्थापना निधि के अंतर्गत 227 करोड़ के कार्य मार्च महा में प्रारंभ किए जाएंगे इसके लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत धरातल पर कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे, जिसके लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई सभी निर्माण के अधिकारियों व टीम को निविदा प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आंतरिक गलियों में भी नए कार्य करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, प्रमुख कार्यों में सौंदर्य करण के कार्यों को भी शामिल किया जा रहा है लगभग 6 करोड़ से शहर में सौंदर्य करण का कार्य मार्च माह में प्रारंभ कराया जाएगा, नगर आयुक्त द्वारा अवस्थापना के साथ-साथ अन्य मद से होने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई जिसमें एस डब्लू एम के अंतर्गत 32 करोड़ 40 लाख से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु प्रारंभ होने वाले कार्यों के बारे में भी बताया गया, एयर क्वालिटी के अंतर्गत 30 करोड़ 89 लाख के कार्य कराए जाएंगे जिसमें मोहन नगर, वसुंधरा, कवि नगर तथा सिटी जोन में सड़क सुधार के कार्य होंगे निविदा आमंत्रित की जा चुकी है बताया गया' इंदिरापुरम अवस्थाना के लिए 17 करोड़ 41 लाख के कार्य इंदिरापुरम के वार्डों में कराए जाएंगे जिसमें नाला निर्माण के कार्यों को भी शामिल किया गया है इंदिरापुरम क्षेत्र वासियों को जल निकासी के लिए समाधान दिया जाएगा ध्यान में रखते हुए नाला निर्माण के कार्य भी शामिल किए गए हैं । नगर आयुक्त द्वारा उपस्थित समस्त निर्माण विभाग के अधिकारियों को चल रहे कार्यों पर बारीकी से नजर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया, वार्डों में चल रहे कार्य स्थलों पर निरीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिए गए। गाजियाबाद को

● चल रहे कार्यों पर बारीकी से नजर रखें अधिकारी : नगर आयुक्त

विकास की रफ्तार देने के लिए गाजियाबाद नगर निगम लगातार शहर हित में कार्य कर रहा है आगामी माह में 227 करोड़ के कार्यों को प्रारंभ करने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है पांचो जोन में मुख्य मार्गों के साथ-साथ वार्डों की आंतरिक गलियों के सुधार का भी ध्यान रखा जा रहा है वैशाली सेक्टर 5, वसुंधरा सेक्टर 1, वसुंधरा सेक्टर 12, सूर्य नगर 80 फूटा रोड, वसुंधरा सेक्टर 1 आस्था कुंज वाली रोड, भोवापुर गांव, हापुर चुंगी चौक से हरसाँव, एनएच 9 से मेरठ रोड तिराहा, डी पी सी चौक विजयनगर, मेडिकल चौक विजयनगर, लीलावती चौक विजयनगर, सिकंदरपुर कट, सिकंदरपुर कट से दिल्ली बॉर्डर, महरौली गांव कवि नगर, शंकर विहार कवि नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कवि नगर, शास्त्री नगर ए ब्लॉक, शास्त्री नगर जागृति विहार, बम्हेटा, मोरटा हम तुम रोड, हरवंश नगर घुकना मोड, विकास नगर मेरठ रोड, लोहिया नगर रेलवे लाइन पुल के नीचे, पटेल मार्ग पर गुरु तेग बहादुर चौक, साइन उपवन स्थित श्मशान घाट शौचालय, दौलतपुर फ्लावर साइड पटरी, लोहिया नगर सी ब्लॉक, तिगड़ी गोल चक्कर विजयनगर, रघुनाथ पुरी विजयनगर, राहुल विहार विजयनगर, मवई विजयनगर, सुदामापुरी विजयनगर, आदर्श कॉलोनी विजय नगर अंबेडकर नगर विजय नगर, अकबरपुर बहरामपुर विजयनगर, शिव विहार बिहारीपुर विजयनगर, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन तो मोहननगर, मोहन नगर सिकंदरपुर पुलिस चौकी, राजेंद्र नगर सेक्टर 5 राधेश्याम पार्क के चारों तरफ, राजेंद्र नगर चुना भट्टी रोड, संजय नगर फ्लाईओवर, साहिबाबाद गांव, सिख रोड कवि नगर पांच नंबर भट्टा, करपुरीपुरम कवि नगर,अर्थला गांव मोहननगर, रामपुरी वसुंधरा जोन, रामप्रस्थ वसुंधरा जोन वसुंधरा सेक्टर 13, संजय नगर संयुक्त जिलाअस्पताल, प्रताप विहार बिछल द्वारा विजय नगर, व अन्य क्षेत्र के सड़क सुधार इंटरलॉकिंग टाइल, नाली मरम्मत में नालों का निर्माण कार्य शामिल किया गया है, प्रमुख कार्यों में बायोडायवर्सिटी पार्क के विभिन्न जन उपयोगी सुविधाओं के कार्यों को भी शामिल किया गया है।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने सुनी जन शिकायतें

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई की गयी। जन सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से सम्बंधित प्रार्थना/शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को शासन के मंशा अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा जमीन से संबंधित समस्या को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय सुनिश्चित कराएं जाने के निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि विरासत के आधार पर आवेदित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है।

अब तक विरासत के आधार पर आवेदित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों जिनमें पुलिस एवं तहसील की जाँच आख्यायें प्राप्त होकर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण हो चुकी थी, को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। विरासत के आधार पर आवेदित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के सम्बन्ध में आवेदक किसी भी कार्यदिवस में शस्त्र अनुभाग, कलेक्ट्रेट गाजियाबाद में सम्पर्क कर सकते है तथा शस्त्र लाइसेंस सम्बन्धी प्रकरणों में किसी भी प्रकार की शिकायत/असुविधा होने पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है। जनसुनवाई के दौरान एडीएम ई, एडीएम एल/ए, जिला सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों हेतु निःशुल्क आयुष्मान कार्ड की सुविधा

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी के निदेशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान चिन्हित सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। आप सबसे अनुरोध है कि 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी लोग इस योजना से जुड़ने के लिए अपना आयुष्मान कार्ड सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों पर निःशुल्क बनवा सकते हैं। यह कार्ड आप स्वयं भी बना सकते है। ध्यान रखें- इस कार्ड को बनाये जाने हेतु आधार कार्ड एवं उससे लिंक मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है। आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु लिंक https://beneficiary.nha.gov.in और AYUSHMAN APP (DOWNLOAD FROM PLAY STORE) से डाउनलोड कर सते हैं।

परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध चलाया सघन अभियान

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था सुदृढ करने तथा सड़कों को क्षति से बचाने के उद्देश्य से दिये गये निदेर्शों के क्रम में परिवहन विभाग, गाजियाबाद द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान जनपद के मोहननगर, इन्द्रापुरम, मेरठ रोड, पेरीफेरल रोड आदि क्षेत्रों में चलाया गया।

उक्त अभियान में प्रवर्तन दलों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक जांच की जा रही है। जांच के दौरान निर्धारित भार क्षमता से अधिक भार लेकर चल रहे वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसी कम में दिनांक 04/05.02.2026 की रात्रि में अभियान के दौरान ओवरलोड/ प्रपत्र समाप्त 25 वाहनों को निरुद्ध किया गया है। साथ ही वाहन स्वामियों एवं चालकों को भविष्य में ओवरलोडिंग न करने के लिए चेतावनी भी दी गई है।

परिवहन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ओवरलोडिंग के कारण सडकों की शीघ्र क्षति होती है, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है तथा आमजन की जान-माल को खतरा उत्पन्न होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा ओवरलोडिंग के विरुद्ध सख्त नीति अपनाई गई है। अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा लापरवाही न हो तथा सभी कार्यवाहियाँ पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपादित की जाएं।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों, चालकों एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें, ओवरलोडिंग से बचें तथा सड़क सुरक्षा में अपना सहयोग प्रदान करें। यह प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती रहेगी। यह अभियान परिवहन विभाग की टीम में अमित राजन राय, मनोज कुमार मिश्रा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गाजियाबाद तथा खनन विभाग से जिला खनन अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी द्वारा चलाया गया।

जनपद में 'आपदा मित्र' बनने का सुनहरा अवसर

गौतमबुद्धनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के दिशा निदेर्शों के अंतर्गत आपदा मित्र परियोजना के तहत 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना, जिसके लिए जनपद से शेष 19 स्वयंसेवकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। चयनित 19 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को 17 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक मुख्यालय राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में ठहरने, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री तथा आवागमन सहित समस्त व्यय एसडीआरएफ द्वारा वहन किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। पात्र स्वयंसेवकों का नामांकन, पंजीकरण एवं अन्य औपचारिकताएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आपदा मित्र के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, जबकि पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मी एवं इंजीनियरों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

जिंदल पब्लिक स्कूल में कराटे वेलफेयर सोसाइटी ने किया आत्मरक्षा शिविर का आयोजन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। लालकुआँ स्थित जिंदल पब्लिक स्कूल में आज कराटे वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष विजय कौशिक ने बताया कि कराटे वेलफेयर सोसाइटी समय-समय पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन करती रहती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे को मार्शल आर्ट्स के दांव-पेंच सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में स्वयं एवं अपने परिवार की रक्षा कर सकें। शिविर का विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी एवं जिंदल पब्लिक स्कूल के संस्थापक रामावतार जिंदल ने रिबन काटकर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में कराटे का अभ्यास सभी के लिए आवश्यक है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का एक प्रभावी माध्यम है, जो शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क को भी मजबूत बनाता है।

● संस्था का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे को मार्शल आर्ट्स के दांव-पेंच सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है

इस अवसर पर संस्था के महासचिव राजीव मुंडेलवाल ने बताया कि कराटे वेलफेयर सोसाइटी अब तक हजारों बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी है। संस्था का लक्ष्य विशेष रूप से बेटियों को इतना सक्षम बनाना है कि वे अकेले बाहर निकलते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और किसी भी प्रकार की बदतमीजी का मुंहतोड़ जवाब दे सकें।

शिविर में संस्था की ओर से कोच तुषार ठाकुर, हरि किशन एवं प्रगति सिंह ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के दौरान जिंदल पब्लिक स्कूल का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा।

भारत मंडपम में प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी की स्टालों का संजीव गुप्ता व राजीव गुप्ता ने किया उद्घघाटन

प्लास्टिक उत्पादों के लिए दाना बनाने वाली कंपनी प्लास्टीन व एसएसपीएल की स्टालों का किया उद्घाटन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

नई दिल्ली। नयी दिल्ली के भारत मंडपम में प्लास्ट इंडिया ऑगेनाइजेशन के द्वारा 5 फरवरी से 10 फरवरी तक प्लास्टिक से संबंधित उत्पादों एवं उनकी संबंधित मशीनों की कंपनी हेतु एक बडे.स्तर पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में भारत सहित चीन, जर्मनी, ताईवान सहित अनेक देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 1700 स्टॉलें लगाई है। इस व्यापारिक प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य प्लास्टिक से संबंधित कच्चे माल और संबंधित मशीनों की कंपनियों को एक ही छत्त के नीचे एकत्रित करके देश के प्लास्टिक उद्योग जगत को प्रोत्साहित करना रहता है।

बृहस्पतिवार को समरकूल और थमोर्कूल के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता और राजीव कुमार गुप्ता ने भी इस प्रदर्शनी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली दो बड़ी कंपनी प्लास्टीन व एसएसपीएल की स्टॉलों का फीता काटकर उद्घाटन किया। कंपनी के एम डी पंकज गोयल, मनीष गोयल, सचिन गोयल सहित एसएसपीएल के एमडी राजेश बंसल, मोहित बंसल ने पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए गुप्ता बंधुओं का स्वागत किया। इस अवसर पर संजीव कुमार गुप्ता व राजीव कुमार गुप्ता ने सभी का धन्यवाद देते हुए उनकी उन्नति और प्रगति की कामना की। इस अवसर पर अभिषेक गुप्ता, आशुतोष गुप्ता एवं तनुज गुप्ता भी साथ रहें।

औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता और विकास को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश

औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं और आगामी विकासात्मक कार्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करें: जिलाधिकारी

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उद्योगपतियों की समस्याओं का निस्तारण करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सफाई, सड़कों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने यूपीसीडा सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित सभी बिंदुओं को क्रमवार पीपीटी के माध्यम से बैठक में प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अवैध अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करें जिससे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। साथ ही उद्योगों को आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत होकर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होने कहा कि उक्त क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों के लिए बजट आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे उद्योगों का संचालन सुचारु रूप से हो सके और निवेश को प्रोत्साहन मिले। इस अवसर पर बैठक में अपर जिलाधिकारी एल/ए, अपर जिलाधिकारी (नगर) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारी साझा की।

प्रभात नमकीन एंड स्नैक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को दुबई में मिला बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

नई दिल्ली। व्यापार को बढ़ावा देने की पहल तहत अमर उजाला बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का भव्य आयोजन दुबई के रेडिसन ब्लू डीरा क्रीक में सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित समारोह में प्रभात नमकीन एंड स्नैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को उनके उत्कृष्ट व्यावसायिक योगदान के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया। इस समारोह में रिटेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 35 उत्कृष्ट उद्यमियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमाल सईद अहमद बुजंजाल अल एवं विशिष्ट अतिथि कैप्टन प्रदीप सिंह ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं के उद्योग विकास और सामाजिक प्रभाव में योगदान की सराहना की।समारोह में भारत एवं विदेशों से आए प्रतिष्ठित उद्यमी, शिक्षाविद्, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बिजनेस लीडर्स की उल्लेखनीय उपस्थिति रही और जिनकी सक्रिय भूमिका से आयोजन अत्यंत सफल रहा। दुबई को इस आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया, जो अपनी वैश्विक कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक अवसंरचना और व्यापार-अनुकूल वातावरण के लिए जाना जाता है। बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स का उद्देश्य भारतीय उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सतत विकास के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है। दुबई संस्करण ने एक बार फिर सीमाओं से परे उत्कृष्टता को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता को मजबूती से स्थापित किया।

सोन नदी सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन का मामला गरमाया रुद्रा माइनिंग कंपनी पर आरोप

बड़े पैमाने पर बालू-मौरंग का अवैध खनन वन विभाग और जिला प्रशासन पर उठ रहे सवाल

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। महलपुर भगवा क्षेत्र में स्थित सोन नदी के सेंचुरी एरिया (रेडिया क्षेत्र) में अवैध खनन का खेल खुलेआम बेखौफ तरीके से चल रहा है। आरोप है कि मे0 रुद्रा माइनिंग कंपनी के लीज की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर बालू-मौरंग का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के संरक्षित क्षेत्र में भारी-भरकम पोकलेन मशीनें और बड़ी-बड़ी नावों के सहारे दिन-रात खनन कार्य जारी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार,यह पूरा अवैध खनन सोन नदी के उस हिस्से में हो रहा है, जिसे सेंचुरी क्षेत्र घोषित किया गया है और जहां किसी भी प्रकार का खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अवैध खनन में लगे लोग स्वयं को पर्यावरण रक्षक बताकर घूम रहे हैं,जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत बताई जा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि गुरमा वन विभाग पर गहरी कुम्भकर्णीय नींद में सोने के आरोप लग रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा आम है कि गुरमा रेंजर की कथित कृपा से ही सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन का यह खेल फल-फूल रहा है।

यदि वन विभाग अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करता तो संरक्षित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ संभव नहीं होतीं।अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है अवैध खनन हो रहा है बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पूरा खेल किसके संरक्षण में चल रहा है यह जिला प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है।

यदि सब कुछ प्रशासन की नजर में है तो अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जिला प्रशासन किसी दबाव या मजबूरी में हाथ पर हाथ धरे बैठा है ? सूत्रों की मानें तो इस अवैध खनन के पीछे कुछ प्रभावशाली और सफेदपोश माननीय लोगों के संरक्षण की भी चर्चा जोरों पर है। यही कारण बताया जा रहा है कि खनन माफिया न तो कानून से डर रहे हैं और न ही कार्रवाई का भय उन्हें रोक पा रहा है। आम लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार में अब कानून का डर समाप्त हो गया है,या फिर प्रभावशाली संरक्षण के आगे सिस्टम बेबस नजर आ रहा है।

सोन नदी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में हो रहा यह अवैध खनन न केवल प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन, वन विभाग और शासन स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हैं, या फिर यह अवैध खनन यूँ ही संरक्षण के साए में चलता रहेगा।

सेक्टर 105 की आहना का राष्ट्रीय योगासन में स्वर्णिम प्रदर्शन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। आर० डबल्यू० ए० अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने बताया सेक्टर 105, नोएडा की निवासी आहना, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा हैं, ने राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर नोएडा शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है।

यह प्रतियोगिता 30 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक कोर्ट फील्ड, धीमाजी, असम में आयोजित हुई। आहना ने इस प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आहना पहले भी राष्ट्रीय और एशियन स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

उनकी सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और उनकी कोच राखी सरकार का मार्गदर्शन रहा है। आर० डबल्यू० ए० सेक्टर 105 और निवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ में कटौती से परिधान निर्यातकों को बड़ी राहत: ललित ठुकराल

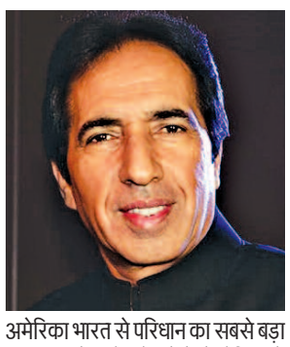

नोएडा(स्वास्तिक सहारा)। अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन ललित ठुकराल ने अमेरिका द्वारा भारतीय परिधान उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ में 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारतीय परिधान उद्योग के लिए एक बड़ी राहत और संजीवनी बताया। ललित ठुकराल ने कहा कि टैरिफ में कटौती की यह खबर परिधान निर्यातकों में नई उम्मीद लेकर आई है। नोएडा से हर साल लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का परिधान निर्यात अमेरिका को किया जाता है, जो देश के कुल परिधान निर्यात का लगभग 30झ 35 प्रतिशत है। अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण परिधान उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा आय पर असर पड़ा बल्कि रोजगार सृजन भी प्रभावित हुआ और कई निर्यातक गंभीर संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से परिधान का सबसे बड़ा आयातक देश है और ऐसे में टैरिफ में यह कटौती भारत को 30 अरब अमेरिकी डॉलर के परिधान निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। साथ ही यह कटौती भारत को अमेरिका को परिधान निर्यात करने वाले देशों में सबसे कम टैरिफ वाला देश बना देगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी।

सरकारी धन का खुला बंदरबांट: हैंडपंप मरम्मत के नाम पर हजारों रुपए का फर्जी भुगतान का आरोप

हैंडपंप मरम्मत के नाम पर हो रहा लगातार भुगतान, फिर भी खराब पड़े कई हैंडपंप

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। विकास खंड नगवां में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर हर वर्ष हजारों रुपए का भुगतान किया जाता है लेकिन अगर धरातल पर देखा जाय तो कहानी कुछ और बयां कहती है सरकारी धन के बंदरबांट में सरकारी तंत्र पूरी तरह से मिला हुआ है जीरो टार्लेस की नीति को ठेंगा दिखाते हुए ग्राम प्रधान पंचायत सचिवों के सहयोग से प्रति हैंडपंप मरम्मत के नाम पर अठ्ठारह से बीस हजार रुपए का भुगतान धड़ल्ले से होता रहा है धरातल पर इसकी क्या स्थिति है इसको जानने या देखने का जहमत नहीं उठाते है ब्लॉक स्तरीय अधिकारी।

विकास खण्ड नगवां में कुछ एसे ग्राम पंचायत सचिव है जो अपने गांव क्षेत्र में जाते नहीं ऑफिस में बैठकर फरमान करते हैं फोन तो उठाना उचित ही नहीं समझते ग्रामीण बेचारे परेशान व बेबस होकर रह जा रहे हैं ताजा मामला ग्राम पंचायत सिकरवार और सेमरिया के गावों में कई ऐसे हैंडपंप है जो आज भी खराब पड़े हैं जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर हैंडपंप है वे लोग कई बार ग्राम प्रधान से कह चुके है लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र को ग्रामीणों की आवाज सुनाई नहीं देती है जबकि बिना किसी स्थान को इंगित किए लगातार हैंडपंप मरम्मत के नाम पर भुगतान बदस्तूर जारी है। किसके दरवाजे के सामने का हैंडपंप मरम्मत हुआ है ये नहीं दशार्या जाता है सिर्फ हैंडपंप मरम्मत पर भुगतान कर दिया जाता है सूत्रों से जानकारी के अनुसार हैंडपंप मरम्मत में भी संबंधित द्वारा राजनैतिक द्वेष की भावना से ओत प्रोत प्रधान द्वारा हैंडपंप मरम्मत में भी भेदभाव कर रहे हैं। जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है ग्राम प्रधान सरकारी धन को अपना निजी धन समझ बैठे हैं और उसके खर्च में भेदभाव कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एडीओ पंचायत नगवां से सेलफोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने ने कार्यवाई का भरोसा दिलाया है।

टीईटी प्रकरण को लेकर जंतर मंतर पर धरना, ज्ञापन सौपा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चे ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गोरिवर्कर महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में जंतर मंतर दिल्ली पर धरना देकर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया। उपरोक्त धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने भी घटक संगठन होने के नाते प्रतिभागिता की। बता दे कि अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा टीईटी प्रकरण पर लगातार संघर्ष कर रहा है।

संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मेरठ मंडल अध्यक्ष उमेश राठी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर निरंजन सिंह नागर, महामंत्री शकरुद्दीन, उपाध्यक्ष संजय भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष दनकौर सत्यवीर सिंह नागर, फरियाद अली, मुनेश शर्मा, अवनीश चौहान सहित सैकड़ो शिक्षकों ने जनपद गौतम बुद्ध नगर से प्रतिभाग किया।

रामपुर बरकोनिया नवागत थानाध्यक्ष विनोद कुमार का समाजसेवीओ ने किया भव्य स्वागत

अंगवस्त्र फूल माला पहनाकर लोगों किया सम्मानित

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। रामपुर बरकोनिया थानाध्यक्ष के पद पर विनोद कुमार की नियुक्ति होने पर थाना क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर की है इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता ने थाना परिसर में पहुंचकर नवागत थानाध्यक्ष विनोद कुमार का गर्मजोशी से समाजसेवीओं राजकुमार उर्फ (चंदन) सुभम पाठक नें फूल-मालाएं पहनाकर अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान उपस्थित लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में कानून- व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी एसओ ने जनता को न्याय व सुरक्षा का भरोसा दिया।थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने सम्मान के लिए सभी सम्भ्रांत जनो का आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेंगे।

इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, युवा एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे विनोद कुमार सोनभद्र यातायात प्रभारी निरीक्षक रहते हुए बेहतर कार्य किए थे एसपी अभिषेक वर्मा ने विनोद कुमार को घोरावल कोतवाली की जिम्मेदारी सौंप थी अब विनोद कुमार को रामपुर बरकोनिया थाना की कमांन एसपी अभिषेक वर्मा ने दी है

सेक्टर 100 के निवासियों की समस्याओं का समाधान अब आसान: निखिल सिंघल

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। फेडरेशन सेक्टर 100 को मॉडल सेक्टर बनाने के लिए नोएडा हाईराइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल ने घोषणा की है कि वह हर शनिवार को 2-4 बजे के बीच अपने कार्यालय में एल्डेको अमानत्रन एज में निवासियों से मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य सेक्टर 100 के निवासियों की समस्याओं का समाधान करना और उनके जीवन को आसान बनाना है। सेक्टर से संबंधित मुद्दों जैसे कि सफाई, रोड रिपेयर, स्ट्रीट लाइट्स, ग्रिड सप्लाई इज्यू, पानी की कमी, स्थानीय प्रशासन के मुद्दे, ऑथोरिटी पार्क के मुद्दे आदि पर फोलोअप कर रहे निवासी अब हर शनिवार को 2-4 बजे के बीच निखिल सिंघल से मिल सकते हैं।निखिल सिंघल ने कहा की हम अपने सेक्टर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी निवासियों को आगे आकर अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ मिलकर, हम एक मॉडल सेक्टर बना सकते हैं। आम जनता और मार्केट के लोग भी किसी भी प्रकार के मुद्दे के लिए निखिल सिंघल से मिल सकते हैं। सेक्टर 100 से संबंधित सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। निखिल सिंघल ने आगे कहा की हमारा उद्देश्य सेक्टर 100 को एक ऐसा स्थान बनाना है जहां लोग सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक जीवन जी सकें। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और निवासियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग: विकास नहीं, जनता से वसूली का एक्सप्रेस कॉरिडोर

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। युवा समाजसेवी लोकेश उपाध्याय ने वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर जारी टोल वसूली को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मार्ग आज विकास का नहीं, बल्कि जनता से व्यवस्थित वसूली का मॉडल बन चुका है।

लोकेश उपाध्याय ने कहा कि जिस सड़क का निर्माण चेतक कंपनी द्वारा कराया गया और जो चार राज्यों को जोड़ती है, वही सड़क आज भारत की सबसे महंगी सड़कों में गिनी जा रही है। सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर 440 टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि यह वसूली 2014 से लगातार जारी है और सड़क आज तक पूरी तरह मानकों के अनुसार तैयार नहीं हो सकी है।

उन्होंने सवाल उठाया–"जब हाईवे अधूरा है, तो टोल वसूली आखिर किस आधार पर की जा रही है ?" लोकेश उपाध्याय ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार टोल वसूली से पहले सड़क का कार्य पूर्ण होना, सेफ्टी ऑडिट, रेस्ट एरिया, गेस्ट हाउस, शौचालय, पार्किंग, स्पीड ब्रेकर से पहले चेतावनी संकेत और पर्याप्त साइनेज अनिवार्य हैं। लेकिन वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर इनमें से कोई भी बुनियादी सुविधा मौजूद नहीं है।

उन्होंने कहा कि–न यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है ,न शौचालय ,न सुरक्षा के इंतजाम, न ब्रेकर से पहले चेतावनी संकेत इसके बावजूद चार टोल प्लाजा पूरी सख़्ती से टोल वसूली कर रहे हैं, जो नियमों और संविधान दोनों का खुला उल्लंघन है। लोकेश उपाध्याय ने कहा कि अउढ कंपनी यात्रियों को कोई मूलभूत सुविधा देने में पूरी तरह विफल रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और सिस्टम आँख मूँदकर इस अवैध वसूली को संरक्षण दे रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट माँग करते हुए कहा–"जब तक वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पूरी तरह सरकारी मानकों के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सोनभद्र जिले की प्राइवेट गाड़ियों को तत्काल टोल-मुक्त किया जाए और टोल वसूली पूरी तरह बंद की जाए।"

अंत में उन्होंने कहा–"अगर विकास के नाम पर सिर्फ टोल बढ़े और सुविधाएँ शून्य हों, तो उसे विकास नहीं बल्कि जनता की व्यवस्थित लूट कहा जाएगा। युवा और आम नागरिक इस अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

आईएमएस नोएडा में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। सेक्टर 62 स्थित आईएमएस नोएडा के स्कूल ऑफ आईटी ने सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के प्रति छात्रों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान बतौर वक्ता सी-डैक के साइबर सिक्युरिटी इंजिनियर शुभम त्रिपाठी ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उभरते साइबर खतरों, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गयी।कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए आईएमएस की डीन प्रोफेसर डॉ. नीलम सक्सेना ने कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सुरक्षित, सतर्क एवं नैतिक तरीके से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉ.विकास धवन ने कहा कि डिजिटल तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता समय की आवश्यकता बन गई है। छात्रों को संभावित खतरों से अवगत रहने के साथ-साथ जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की जरूरत है। शुभम त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी डिजिटल दुनिया का सक्रिय हिस्सा हैं, इसलिए अपनी ऑनलाइन पहचान और डेटा की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के साइबर परिदृश्य में केवल सिस्टम का उपयोग जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा संरचना को समझना भी उतना ही जरूरी है

विराट रूद्र महायज्ञ के लिए 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज किया गया स्थापित

6 मार्च से होने वाली यज्ञ में कलश यात्रा शिव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। चतरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरिया में वृहस्पतिवार को विराट रूद्र महायज्ञ के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित किया गया। 6 मार्च को कलश यात्रा कलश स्थापना के बाद यज्ञ शुरू होगी। यज्ञ की पूणार्हुति 14 मार्च को भंडारे के साथ होगी।जानकारी के अनुसार भिक्षुक भिखारी,जंगली दास,रमाशंकर गिरी जी महाराज की देखरेख में यह यज्ञ हो रही है। आचार्यगण देवी प्रसाद पांडेय, सतीश पांडेय, दीपक पांडेय व योगेश तिवारी के जरिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित किया गया है।जंगली बाबा ने बताया कि मुख्य यजमान प्रवीण मिश्रा,सरिता मिश्रा, कृष्ण कुमार पुजारी व प्रभावती देवी हैं। 6 मार्च को कलश यात्रा निकलेगी और कलश स्थापना के बाद विराट रूद्र महायज्ञ शुरू होगी। 9 मार्च को शिव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 14 मार्च को यज्ञ की पूणार्हुति के साथ भंडारा चलेगा

जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में था बंद

जिलाधिकारी नें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीएम कराने का निर्देश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जिला जेल में निरुद्ध एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक कैदी एनडीपीएस एक्ट के मामले में सोनभद्र जिला जेल में बंद था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भोर में जेल प्रशासन गंभीर अवस्था में कैदी को लोढ़ी स्थित मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही लोढ़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज.दीया मृतक की पहचान रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के उरमौरा निवासी राधेश्याम यादव उम्र 26 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई है। कैदी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर राधेश्याम की हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जिला जेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

डीडीआरडब्लयूए फेडरेशन ने सीईओ से की मुलाकात, उठाई 6 प्रमुख समस्या

आपदा के वक्त हैलीकॉप्टर का उपयोग किया जाए : ठा. एन.पी. सिंह

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। डीडीआरडब्लयूए फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करूणेश से मुलाकात कर 6 बिन्दुओं पर उनसे चर्चा की। सेक्टर-150 के हादसे के बाद लोगों के जान माल की रक्षा के लिए डीडीआरडब्ल्यूए ने सीईओ को दो पत्र भी प्रेषित किए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया गया कि दोनों पत्र के सभी बिंदुओं पर प्राधिकरण द्वारा तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। क्यूआरटी टीम गठित करने पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी वर्क सर्कल को आदेशित किया गया है कि वह अपने एरिया की आरडब्ल्यूए से नियमित हर महीने मीटिंग करेंगे और उसकी मिनिट्स आफ मीटिंग बनाकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ऑफिस में सबमिट करेंगे और आरडब्ल्यूए को भी उपलब्ध करवाएंगे। गलत यू टर्न और रोड इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने हेतु एक टीम का गठन किया जाएगा और नोएडा शहर की आरडब्ल्यूए और फेडरेशन को भी सम्मिलित किया जाएगा। नालो को कवर करने हेतु सभी वर्क सर्कल को आदेशित कर दिया गया है और वह इस पर कार्य कर रहे हैं जो भी आरडब्ल्यूए इसमें सहयोग करेगी और राय देगी उस पर कार्य किया जाएगा। हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने पर प्रशासन शासन और अपनी टीम से चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रिकल बसो के मुद्दे पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया की 20 बसे 15 दिनों के अंदर ही शुरूआत करवाने पर मंथन किया जाएगा यह एक अत्यधिक आवश्यक पॉइंट है जिस पर प्राधिकरण को कार्य करने की आवश्यकता है।

सम्पादकीय

अमरीका में 'मेड इन इंडिया'

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न तो टैरिफ 50 फीसदी से घटा कर 18 फीसदी करने का निर्णय अचानक लिया और न ही भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा एकदम की। ट्रंप प्रशासन तब से विमर्श और मंथन कर रहा था, जब भारत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ 'मुक्त व्यापार समझौते' करने में सफल रहा। राष्ट्रपति ट्रंप अपने कुछ नीतिगत फैसलों और 'दादागीरी' के कारण भी घरेलू स्तर पर और वैश्विक संदर्भों में विरोध झेल रहे थे, लिहाजा अकेले पड़ते जा रहे थे। भारत–अमरीका के रणनीतिक संबंध किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मोहताज नहीं हैं। वे निरंतर और स्वाभाविक हैं, क्योंकि वैश्विक समीकरण ही ऐसे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार समझौते की घोषणा की और फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं के संबंध 'प्यारे दोस्त' वाले भी हैं, दोनों एक–दूसरे को 'ताकतवर' भी मानते हैं, लेकिन परस्पर–विरोधी फैसले भी लेते हैं, अंततः रणनीतिक साझेदार मानने लगते हैं। बहरहाल भारत–अमरीका के बीच व्यापार समझौता हुआ है। इसकी बातचीत बड़ी लंबी चली है, समझौता खटाई में भी पड़ता गया है, तीखे विरोधाभास रहे हैं, अंततः समझौते की घोषणा की गई है। हालांकि समझौते का पूरा मसविदा, तमाम ब्यौरे अभी तक सार्वजनिक नहीं हैं, क्योंकि समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं और दोनों देशों का 'साझा बयान' भी प्रतीक्षित है। संभवतः इसी सप्ताह यह औपचारिकता भी निपटा ली जाएगी, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसा बयान दिया है। व्यापार समझौता हुआ है, तो जाहिर है कि अब 30 ट्रिलियन डॉलर वाली दुनिया की सबसे बड़ी, ताकतवर अर्थव्यवस्था के बाजार में 'मेड इन इंडिया' सामान और उत्पादों के बिकने का रास्ता साफ हो गया है। भारत को वस्त्र, रेडिमेड कपड़े, रसायन, ऑटो, कालीन, आईटी हार्डवेयर, फार्मा, रत्न–आभूषण, पेट्रो उत्पाद, लोहा–इस्पात, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, तांबा, चमड़ा–जूते और फर्नीचर आदि के क्षेत्र में फायदा होगा। 'व्यापार समझौता' कितना सकारात्मक और फलदायक है, वह इसी से स्पष्ट है कि 8 सालों में 'रुपया' पहली बार 122 पैसे चढ़ा है और अब एक डॉलर 90.27 रुपए तक लुढक आया है। शेयर बाजार में निवेशकों ने एक ही दिन में 12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। विदेशी निवेशक और एफआईआई एक बार फिर भारत में अपने निवेश बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय और घोषणा का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें 'वाचाल दावों' से परहेज करना चाहिए। मसलन–उन्होंने दावा किया है कि भारत ने 500 अरब डॉलर (करीब 45.15 लाख करोड़ रुपए) के अमरीकी उत्पादों की खरीद का संकल्प लिया है। इनमें ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक–प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। दरअसल भारत का कुल वैश्विक आयात 721 अरब डॉलर का है। भारत का आम बजट भी 53.47 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से 45 लाख करोड़ रुपए अकेले अमरीकी उत्पादों पर कैसे खर्च किए जा सकते हैं?

दैनिक राशिफल

मेष: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ: इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।

शत्रु सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य कमजोर होगा। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बेरोजगारी दूर होगी। लाभ होगा।

मिथुन: का, की, कु, घ, ङ:, छ, के, को, हा।

पुराना रोग उभर सकता है। शोक समाचार मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

कर्क: ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।

यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। घर–बाहर पूछ–परख रहेगी। लाभ होगा।

सिंह: मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।

पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। मान बढ़ेगा।

कन्या: टो, पा, पी, पू, ष, ण:, ठ, पे, पो।

रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे।

तुला: रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।

ऐश्वर्य पर व्यय होगा। स्वास्थ य कमजोर रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

वृश्चिक: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

लेन–देन में सावधानी रखें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रखें। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कानूनी मामले सुधरेंगे।

धनु: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

राजमान प्राप्त होगा। नए अनुबंध होंगे। नई योजना बनेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी।

मकर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।

पूजा–पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रसन्नता रहेगी।

कुंभ: गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।

पुराना रोग उभर सकता है। चोट व दुर्घटना से बचें। वस्तुएं संभालकर रखें। बाकी सामान्य रहेगा।

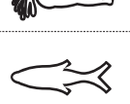

मीन: दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।

बेचैनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म नयी दिल्ली
मोबाइल नंबर - +91 99990 74369

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road, Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

केंद्रीय बजट : आरडीजी संकट से सांसत में प्रदेश सरकार

अनुज आचार्य

कहां तो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ये आस लगाए बैठे हुए थे कि पिछले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भांति 16वें वित्त आयोग द्वारा भी राजस्व घाटा अनुदान मिलने से वे विकास कार्यों को गति और सरकारी कर्मचारियों के प्रति देनदारियों को पूरा कर अगले साल के अंत में होने वाले चुनावों में पूरे दमखम से उतरेंगे और कहां अब केंद्र सरकार ने अपनी बजट घोषणा में आरडीजी को ही एक झटके में खत्म कर हिमाचल सहित कई राज्यों की उम्मीदों को झटका दे दिया है। निश्चित रूप से राजस्व घाटा अनुदान का समाप्त होना हिमाचल की आर्थिक सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। क्या यह माना जाए कि राजस्व घाटा अनुदान का खत्म किया जाना एक राजनीतिक साजिश है? मुख्यमंत्री सुक्खू ने मीडिया के समक्ष आरडीजी ग्रांट पर अपनी व्यथा जाहिर करते हुए इसे हिमाचल की आर्थिकी के लिए 'काला दिन' बताया है। उनका यह भी कहना है कि हिमाचल के पानी, पर्यावरण और ऊर्जा का उपयोग पड़ोसी राज्य अपने फायदे के लिए करें और बदले में हिमाचल को आरडीजी अनुदान से भी वंचित कर दिया जाए। केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल प्रदेश के लिए केवल एक सामान्य बजटीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसके आर्थिक भविष्य पर गहरे प्रश्नचिह्न छोड़ने वाला ऐतिहासिक मोड़ बन गया है। भारत में वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 से प्रचलन (गठन) में है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे हेतु हर 5 साल में गठित किया जाने वाला एक

संवैधानिक निकाय है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करने वाला यह निर्णय हिमाचल जैसे छोटे, पहाड़ी और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य पर पड़ना तय है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, जहां भौगोलिक दुर्गमता, सीमित औद्योगिक आधार, पर्यावरणीय प्रतिबंध और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं विकास की राह को पहले ही कठिन बना देती हैं। ऐसे में राजस्व घाटा अनुदान राज्य के लिए केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्थिरता और विकास योजनाओं की रीढ़ रहा है। 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को लगभग 39127 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान मिला था, जिससे वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और बुनियादी ढांचा किसी तरह संतुलन में रहा। अब 16वें वित्त आयोग ने यह अनुदान पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका अर्थ है कि अगले पांच वर्षों में हिमाचल को लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। इसका सीधा असर राज्य की आर्थिक सेहत, विकास की गति और आम जनजीवन पर पड़ेगा। वित्त आयोग का तर्क है कि राजस्व घाटा अनुदान राज्यों को राजकोषीय सुधारों से दूर करता है और निर्भरता को बढ़ावा देता है। यह तर्क कागजों में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पहाड़ी राज्यों के पास न तो बड़े महानगर हैं, न विशाल औद्योगिक क्लस्टर और न ही कर संग्रह बढ़ाने के असीम अवसर। यहां सडक, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं भी कहीं अधिक लागत में उपलब्ध करानी पड़ती हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखी गई है और 1.40 लाख करोड़ रुपए के वित्त आयोग अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। लेकिन यह राशि राजस्व घाटा अनुदान की भरपाई नहीं कर सकती। स्थानीय निकायों को मिलने वाला धन विशिष्ट उद्देश्यों तक सीमित है और उससे राज्य सरकार के रोजमर्रा के वित्तीय दायित्व पूरे नहीं हो सकते हैं। हिमाचल सरकार ने केंद्र के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी मांगें रखी थीं, कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए सालाना का राजस्व घाटा अनुदान, पहाड़ी राज्यों के लिए अलग ग्रीन फंड, आपदा जोखिम सूचकांक के आधार पर अतिरिक्त राहत और कर्ज सीमा में छूट।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

ललित गर्ग

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां "देर आए, दुरुस्त आए" की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया।

50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं।

यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और "मेक इन इंडिया" को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-

सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को "निरंतर धैर्य का परिणाम" बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है।

अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका।

यदि वाशिंगटन भारत पर एकतरफा दबाव बनाए रखता, तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। ट्रंप द्वारा 500 अरब डॉलर के आयात, शून्य टैरिफ और रूसी तेल त्यागने जैसे नाटकीय दावे इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थे, जिन्हें भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव का मुद्दा बनाया और न ही स्वीकारोक्ति दी। मोदी का इन पर मौन यह दर्शाता है कि भारत इस घटनाक्रम को अंतिम समझौते के रूप में नहीं, बल्कि दिशा-निर्धारण के रूप में देख रहा है। इसके विपरीत, भारतीय विपक्ष इस पूरे प्रकरण में अपनी राजनीतिक अधीरता और रणनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता रहा। उसने टैरिफ को लेकर तात्कालिक लाभ-हानि की भाषा में सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं समय, धैर्य और बहुस्तरीय गणनाओं की मांग करती हैं।

विपक्ष यह समझने में असफल रहा कि कूटनीति में कभी-कभी पीछे हटना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। आज जब अमेरिका को अपना अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा है और भारत फिर से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिख रहा है, तब यह स्पष्ट है कि मोदी की नीति न केवल दबाव से मुक्त थी, बल्कि दूरदर्शी भी। यही नीति भारत को एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सौदे की शर्तें तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह वैश्विक व्यापार में दबाव आधारित राजनीति के अंत का संकेत देता है। लंबे समय से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ, प्रतिबंध और नीतिगत दबावों के माध्यम से छोटे या उभरते देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश करती रही हैं। भारत ने इस प्रवृत्ति को न केवल चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आत्मविश्वास, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी दबाव को संतुलित संवाद में बदला जा सकता है।

भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में यह समझौता एक नए राजनीतिक आभामंडल के निर्माण का भी संकेत देता है। यह संबंध अब केवल रणनीतिक या सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक साझेदारी के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा। दुनिया धीरे-धीरे यह स्वीकार कर रही है कि भविष्य का नेतृत्व किसी एक शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि संतुलित साझेदारियों के माध्यम से उभरेगा, और भारत उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस व्यापारिक प्रगति से मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह साख किसी प्रचार या दावे पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित है। भारत आज विश्व मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्थिरता और सहयोग में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। यही संतुलन उसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग पहचान देता है। महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा भावनात्मक नारों पर नहीं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों, रणनीतिक समझौतों और वैश्विक स्वीकार्यता पर आधारित है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते उस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत को आगे बढ़ने से रोक पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्यापारिक समझौता भारत की परिपक्व कूटनीति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनिया में कोई भी निर्णय केवल आर्थिक गणित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और नेतृत्व की परिपक्वता का भी प्रमाण होता है। देर से लिया गया सही निर्णय, जल्दबाजी में किए गए गलत समझौतों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भारत ने धैर्य रखा, आत्मसम्मान बनाए रखा और अंततः अपने हितों के अनुरूप परिणाम

सत्ता की निष्कंटक राह बरास्ते सुनेत्रा की ताजपोशी

उमेश चतुर्वेदी

उमेश चतुर्वेदी राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है। सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है। फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। पारिवारिक वज्रपात के बीच सिंहासन पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज के सोचने का अपना ढंग है। सियासी हस्तियों से भी उसे सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों को अपनाने की उम्मीद रहती है। सुनेत्रा सामाजिक सवालों से बच नहीं सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी।

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनो पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सुनेत्रा को तत्काल उसका नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार कर लिया गया। शरद पवार भले ही इस सियासी

पटकथा का लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखा है। पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभाई है। सवाल उठ सकता है कि अगर सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं। राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की अगुआई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था। अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गए हैं। अजित के न रहने पर यह संख्या 40 रह गई है। लेकिन बीजेपी की चिंता दूसरी है। शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर होकर उभरते। महाराष्ट्र का यह चाणक्य एक बार फिर स्थापित होता और बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो जाती। शरद पवार इतने प्रभावी और सियासी रूप से तिकड़मी हैं कि बीजेपी के लिए संकट बनकर उभर जाते। उनकी प्रभावी सक्रियता के चलते शिवसेना के गुटों को भी एक करने की वे कोशिश कर सकते थे। भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, लेकिन एकबारगी स्वीकार कर लें कि ऐसा होता तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती। महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली। अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था। अजित की अगुआई वाले जिला परिषद उम्मीदवार उनके न रहने की वजह से थोड़े आशंकित और निराश भी हैं। इस निराशा को कांग्रेस भुना सकती थी। वह एनसीपी के उम्मीदवारों पर डोरे डाल सकती थी और अपने उम्मीदवारों को नए जोश से भर सकती थी। अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरतभरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था। अजित के न रहने के बाद विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है। शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पाए। यह माहौल कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा करती नहीं दिख रही। 2014 के बाद से उसने जिस नैरेटिव युद्ध की शैली को अपनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी युद्ध प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं है कि वह महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की राजनीति के बारे में स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सोचे और स्थानीय समुदायों के लिए उन्हीं के बीच से प्रभावी नेतृत्व उभारे।

रणनीतिक लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है। उसने सुनेत्रा को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। उसने एनसीपी की ओर निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की संभावनाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महाराष्ट्र की सत्ता मानी जाती है। माना जाता है कि कारपोरेट और औद्योगिक जगत पर सबसे ज्यादा पकड़ महाराष्ट्र के सिंहासन की होती है। मौजूदा राजनीति में आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावी है। महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने सुनेत्रा को साधने में देर नहीं लगाई। इसके लिए एनसीपी के ही नेताओं को अपना औजार बनाया और सफल रही। वैसे भी शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनके लिए गुंजाइश कम है। उनके पास सक्रिय रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बेशक वे अब भी कमजोर हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार ही हैं। सुनेत्रा को अपने खेमें में लाकर बीजेपी ने शरद की इस बची-खुची चुनौती भी खत्म करने में कामयाब रही है। सुनेत्रा के साथ से एकनाथ शिंदे के लिए महायुति से बाहर निकलने की सोचना या बीजेपी पर दबाव बढ़ाने का मौका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिंदे के साथ के चलते सुनेत्रा की भी रहेगी। बीजेपी सुनेत्रा के जरिए शिंदे को संतुलित करेगी तो शिंदे के जरिए सुनेत्रा को काबू में रखेगी।

सेहत/स्वास्थ्य

कैंसर के खिलाफ जंग में जागरूकता है सबसे बड़ा हथियार, जानिए इसका इतिहास, महत्व और थीम

विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के लक्षणों, इलाज और रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का इतिहास साल 2000 से जुड़ा है, जब पेरिस में इसकी नींव रखी गई थी ताकि इस घातक बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया जा सके।

कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है। कैंसर का नाम सुनते ही हर एक व्यक्ति डरने लगता हैं। अगर सही समय पर कैंसर का पता चल जाए, तो इसका इलाज संभव वरना इसे बचना नामुमकिन। आमतौर पर इसका इलाज भी काफी महंगा है, कई बार होता है कि पैसे के अभाव के कारण मरीज का सही से इलाज नहीं हो पाता है। एनसीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें कैंसर सेल्स तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलने लगते हैं।

ये सेल्स शरीर में गांठ बना सकती और आसपास के हेल्दी टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि, ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) जैसे कुछ कैंसरों में गांठ नहीं बनती। दरअसल, हर साल लाखों की संख्या में लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसी कारण से कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए हर साल विश्वभर में कैंसर दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। जानें इसका इतिहास, थीम और महत्व।

क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस?

गौरतलब है कि कैंसर का लाइलाज नहीं है, अगर समय पर पहचान और सही इलाज हो। इसके साथ ही यह मरीजों को मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन देने का संदेश भी देता है। हर साल 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए World Cancer Day मनाया जाता है।

वर्ल्ड कैंसर डे की थीम

आपको बता दें कि, हर साल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा कैंसर दिवस को मनाए जाने के लिए एक विशेष थीम नियुक्त की जाती है। इस साल की थीम है 'United by Unique'। इस थीम का उद्देश्य कैंसर से पीड़ित हर व्यक्ति के निजी यात्रा, जरुरतें और अनुभवों को जोड़ना है। इसे सरल शब्दों में समझें कि यूनाइटेड बाय यूनिक का अर्थ है कि कैंसर से पीड़ित हर मरीज की अपनी कहानी होती है, हालांकि इसके लिए हमें बीमारी पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अनुभवों और जरुरतों पर ध्यान देना जरुरी है।

वर्ल्ड कैंसर डे का इतिहास

विश्व कैंसर दिवस की शुरूआत वर्ष 2000 में पेरिस से हुई थी। 4 फरवरी 2000 को पेरिस में ह्लवर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसरह्व का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ (UICC) ने यह विचार रखा कि साल में एक दिन ऐसा निर्धारित होना चाहिए, जब पूरी दुनिया में कैंसर की रोकथाम, उसके लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसी सोच से विश्व कैंसर दिवस की नींव पड़ी। आज भी कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, अस्पतालों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं।

पर्यटन

वैलेंटाइन मंथ में हनीमून का प्लान, उदयपुर से औली तक ये हैं टॉप 5 रोमांटिक डेस्टिनेशन

"अगर आप भी फरवरी में हनीमून के लिए रोमांटिक और हसीन जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप हनीमून ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।"

शादी की डेट फिक्स होने या फिर शादी के फौरन बाद किसी भी कपल के लिए हनीमून पर जाना एक खास अनुभव होता है। यह वह समय होता है, जब आप एक-दूसरे को करीब से जानते हैं। एक तरह से हनीमून वैवाहिक जीवन की शुरूआत का पल होता है। जब भी कपल्स हनीमून का प्लान बनाते हैं, तो वह ऐसी जगहों को ढूंढते हैं, जो रोमांटिक होने के साथ सुविधाएं भी आसानी से मिल जाएं।

फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे वीक भी पड़ता है। इसलिए इस महीने हनीमून और भी अधिक रोमांटिक हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी फरवरी में हनीमून के लिए रोमांटिक और हसीन जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप हनीमून ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।

उदयपुर

उदयपुर शहर के टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन के अलावा इंडिया के टॉप हनीमून में शामिल रहता है। यहां की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि कई बॉलीवुड के सितारे भी यहां पर वेडिंग के लिए पहुंचते हैं। झीलों के बीच स्थित यह शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगता है।

आप उदयपुर में राजशाही अंदाज में हनीमून मना सकते हैं। फरवरी में गुलाबी सर्दियों के बीच उदयपुर में हनीमून ट्रिप चार चांद लगा देगा। उदयपुर में आप जग मंदिर, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, पिछोला झील, सहेलियों-की-बारी, फतेह सागर झील और मानसून पैलेस जैसी बेहतरीन जगहों पर घूम सकते हैं।

डलहौजी

हिमाचल प्रदेश में अगर आप हनीमून ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं। तो आपको एक बार डलहौजी की खूबसूरती को देखने आना चाहिए। बता दें कि डलहौजी में ही 'मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया' के नाम से फेमस खजियार मौजूद है। यहां पर कई कपल्स हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं।

फरवरी के महीने में यहां पर स्नोफॉल के बीच आपका हनीमून यादगार हो सकता है। यहां पर आप पंचपुला, बकरोटा हिल्स, खाज्जिअर, सतधारा झरना, सच पास और डैनकुंड पीक जैसी मनमोहक जगहों को देख सकते हैं।

अल्लेप्पी

अल्लेप्पी को दक्षिण भारत का स्वर्ग माना जाता है। इस खूबसूरत राज्य में कई मनमोहक और हसीन जगहें मौजूद हैं, जहां पर दर्जन भर से अधिक कपल्स हनीमून के लिए आते हैं। ऐसे में अगर आप फरवरी महीने में दक्षिण भारत की किसी खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर जाना चाहते हैं, तो अल्लेप्पी परफेक्ट डेस्टिनेशन है।

अल्लेप्पी में बैकवाटर्स, झील-झरने, समुद्र तट और खूबसूरत बागान देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप अल्लेप्पी में कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, अल्लेप्पी बीच, कुट्टनाड और वेम्बनाड झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर हाउसबोट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

लक्षद्वीप

अगर भारत में किसी जगह पर समुद्री तट की खूबसूरती मौजूद है, तो उस जगह का नाम लक्षद्वीप है। इस जगह की खूबसूरती का उदाहरण तो भारत के प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं। समुद्र की हसीन लहरों को पसंद करने वाले कपल्स के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट है। यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहां पर आप अगत्ती द्वीप, बांगरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कावारत्ती द्वीप और कल्पेनी द्वीप जैसी बेहतरीन जगहों पर घूम सकते हैं।

औली

अगर आप भी फरवरी महीने में उत्तराखंड की हसीन वादियों में हनीमून का प्लान बना रहे हैं। तो फिर आपको औली जाना चाहिए। इस जगह की खूबसूरती काफी ज्यादा प्रचलित है और इसको उत्तराखंड का स्वर्ग भी बोला जाता है। यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी मनमोहक बर्फबारी के लिए भी फेमस है। यहां पर फरवरी के महीने में भी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। आप यहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आप औली में नंदा देवी, त्रिशूल पीक, गुरसों बुग्याल और चिनाब झील जैसी मनमोहक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

ब्यूटी / फैशन

वैलेंटाइन डे पर पाएं फ्लॉलेस ग्लो, ये आसान मेकअप टिप्स आएंगे काम

अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जाने का प्लान कर रही हैं, तो इस दिन खास तरह से तैयार हों। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सिंपल तरह से मेकअप करने का तरीका बताने जा रहे हैं।

कपल्स के लिए वैलेंटाइन डे काफी खास होता है। इस दिन कपल्स एक-दूसरे को खास होने का एहसास कराते हैं। इस दिन लोग अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाते हैं और साथ में समय बिताते हैं। वैलेंटाइन वीक के आखिरी में यह दिन आता है। जिसका इंतजार प्रेमी जोड़ों को सालभर रहता है। इस दिन लड़कियां खास तौर पर तैयार होती हैं और अपने पार्टनर को इंप्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जाने का प्लान कर रही हैं, तो इस दिन खास तरह से तैयार हों। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सिंपल तरह से मेकअप करने का तरीका बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इन टिप्स को अपनाकर इस खास दिन को अधिक खास बना सकती हैं।

स्किन प्रेप

मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से तैयार करना जरूरी होता है। इसके लिए माइल्ड फेसवॉश से चेहरा धो लें। फिर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें। इससे स्किन हाइड्रेटेड होगी और स्मूद रहेगी।

मेकअप बेस

बेस मेकअप करने से पहले त्वचा पर प्राइमर जरूर लगाएं। इसके बाद अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लगाएं और अच्छे से ब्लेंड करें। फिर फेस पर डार्क सर्कल और दाग-धब्बों को छिपाने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करें। वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करना न भूलें।

आई मेकअप

अपने आई लुक को खास बनाने के लिए आई मेकअप जरूरी है। इसके लिए आप रेड, रोमांटिक पिंक या गोल्डन टोन के आइशैडो लगाएं। आप अपने लुक को बॉसी बनाने के लिए विंग्ड लाइनर या कैट आई लुक कैरी करें। वहीं आई मेकअप में मस्कारा जरूर लगाएं, वरना आपकी आंखें अजीब लगेंगी।

हाइलाइटर

अपने लुक को सॉफ्ट रखने के लिए आप हल्का पिंक या पीच ब्लश अप्लाई करें। इससे आपका लुक फ्रेश लगेगा। वहीं गालों की हड्डी, नाक और ब्राउ बोन पर हाइलाइटर लगाएं। जिससे कि आपका लुक ग्लोइंग लगेगा।

घरेलू नुस्खे

अब आलू उबालने के लिए पानी की नहीं जरूरत, बस एक चुटकी नमक करेगा काम

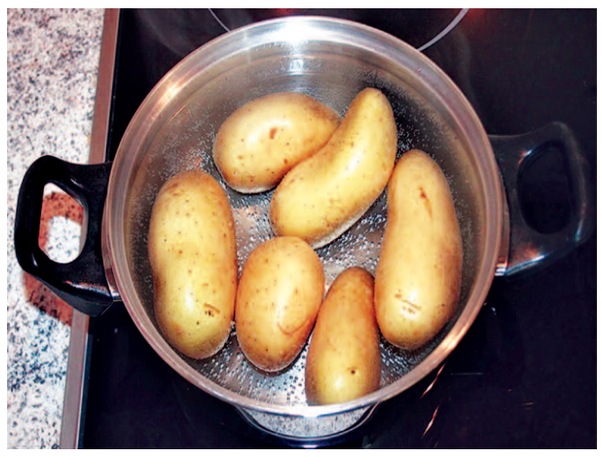

उबले हुए आलू से सिर्फ पराठा नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बन सकता है। आमतौर पर लोग कुकर में पानी के साथ आलू उबालते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि बिना पानी के भी आप आलू उबाल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना पानी के आलू कैसे उबाल सकते हैं।

हमारे यहां पर कई तरह की चीजें खाई और बनाई जाती हैं। वहीं अगर आलू की बात करें, तो यह एक ऐसी सब्जी है, जो सभी चीजों के साथ एडजस्ट हो जाती है। परवल, गोभी, शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों में आलू मिलाया जाता है। वहीं आलू से कई तरह के स्नैक्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कुछ पसंद किया जाता है कि, तो वह आलू का पराठा है। इसको बनाने के लिए आलू को उबालना जरूरी है।

उबले हुए आलू से सिर्फ पराठा नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बन सकता है। आमतौर पर लोग कुकर में पानी के साथ आलू उबालते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि बिना पानी के भी आप आलू उबाल सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना पानी के आलू कैसे उबाल सकते हैं।

ऐसे उबालें बिना पानी के आलू

सबसे पहले जितने आलू की जरूरत है ले लें और उनको अच्छे से धो लें। फिर इनका चाहें तो छिलका भी उतार सकती हैं। लेकिन छिलके के साथ आलू पकाने से उनमें मौजूद पोषक तत्व कम नहीं होते हैं।

आलू को सीधे प्रेशर कुकर में

रख दें और इसमें बिल्कुल भी पानी न डालें।

इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दें और चाहें तो इसमें हल्का सा मसाला भी डाल सकती हैं। इससे आलू में स्वाद आ जाएगा।

अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। वहीं एक सीटी आते ही गैस बंद कर दें। फिर कुकर से अपने आप प्रेशर निकलने दें।

आलू पक गए हैं कि नहीं कैसे करें चेक

जब कुकर का पूरा प्रेशर निकल जाए, तब कम से कम 10 मिनट बाद ढक्कन खोलें। फिर आलू में नुकीली चीज या चाकू लगाकर चेक करें कि आलू पकी हैं या नहीं। अगर नुकीली चीज आसानी से अंदर चला जाए, तो समझ जाएं कि आलू पूरी तरह से पक चुके हैं।

इस तरीके से आलू की अपनी नमी और कुकर की भाप भी उसे नरम बना देती हैं। पानी न होने के कारण आलू में एक्स्ट्रा पानी नहीं आता है। इससे इसका स्वाद भी नहीं बिगड़ता है।

सही तरीका

बता दें कि आलू उबालते समय सही साइज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। छोटे आलू जल्दी पक जाते हैं और बड़े आलू थोड़ा अधिक समय लेते हैं।

अगर आलू ज्यादा बड़े हैं, तो इनको आधा काट लेना सही है। इससे सी आलू एक साथ पक जाते हैं।

किसानों को अब 5 मिनट में ई-केसीसी से ऋण: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन

सीएम की घोषणा

- डिजिटल गवर्नेंस से किसानों को राहत, एफपीओ, सहकारिता व एमएसएमई से मजबूत हुई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
- लघु-सीमांत किसानों को कम ब्याज पर ऋण से मिला संबल, सहकारिता के डिजिटलीकरण से बढ़ी पारदर्शिता व जवाबदेही

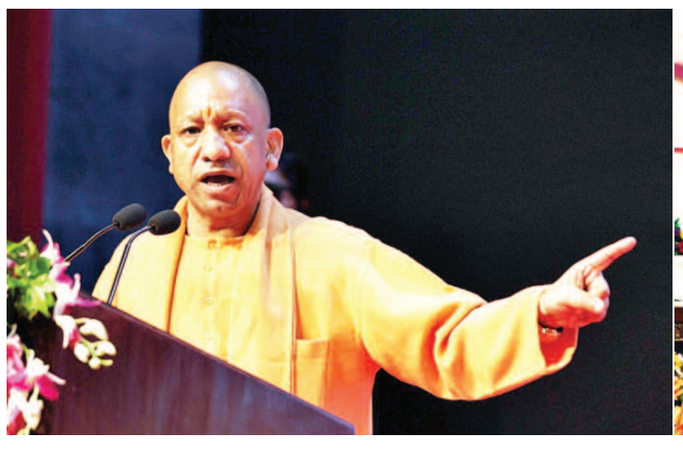

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृति की तस्वीर ही बदल दी है। अन्नदाता किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण लेने जाता था, तो 25 दिन से लेकर एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा कृषि ऋण 3 लाख करोड़ है, यह पहले की तुलना में 13 फीसदी बढ़ा है। यही सुशासन है और इसी दिशा में हमें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग खेती में कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) को मंच पर सम्मानित भी किया।

दिव्यांग और महिला नेतृत्व वाले एफपीओ बने प्रदेश के लिए रोल मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए, वे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ, जिसमें 1,005 सदस्य हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पहले कमजोर माना जाता था, दिव्यांगजनों ने अपनी मेहनत और क्षमता से नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आंखें खोलने वाला काम है और इसके लिए वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा की 750 महिलाओं वाली सरसों उत्पादन कंपनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने स्वयं उनकी प्रदर्शनी देखी है। किस तरह मस्टर्ड ऑयल को प्रोसेसिंग से जोड़कर महिलाओं ने बेहतर मुनाफा कमाया, यह पूरे प्रदेश के लिए सीख है। सरकार इस तरह के प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी।

एमएसएमई को नई जान, ओडीओपी बना यूपी की पहचान

सीएम योगी ने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र भी बदल रहा है। 'सहकार से समृद्धि की ओर' के विजन के तहत डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से सहकारी संस्थाओं में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो विश्व बैंक के साथ एग्री-टेक के क्षेत्र में काम कर रहा है। कृषि, एमएसएमई, महिला, एग्री-टेक और युवा उद्यमिता आज सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में माफिया हावी था।

रिजर्व बैंक ने 16 जिला सरकारी बैंकों को डिफाल्टर घोषित कर बंदी का आदेश कर दिया था। आज हमारी सरकार में इन्हीं 16 में से 15 बैंक प्रॉफिट में आ चुके हैं और 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में भी एक समय ऐसा था, जब उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका था। हस्तशिल्प और निर्यात लगभग ठप थे और एमएसएमई सेक्टर बंदी की कगार पर खड़ा था।

हमारी सरकार ने इसे एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख का सुरक्षा बीमा दे रहा है। आज प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स कार्यरत हैं और लगभग 3 करोड़ परिवार इसी सेक्टर पर निर्भर हैं। टेक्नोलॉजी, मार्केट, पैकेजिंग और डिजाइनिंग से जोड़कर ओडीओपी को एक ब्रांड बनाया गया है। परिणाम यह है कि प्रदेश का निर्यात 84 हजार करोड़ से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, तो राष्ट्राध्यक्षों को ओडीओपी प्रोडक्ट्स उपहार में देते हैं।

एफपीओ की मजबूती से बदली यूपी की कृषि अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश के एफपीओज की ताकत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस ट्रेड शो में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एफपीओ और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का क्रेडिट-डेबिट रेशियो (सीडी रेशियो) 9 वर्षों में 43 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है। लक्ष्य है कि इसी साल 31 मार्च तक इसे 62 प्रतिशत और 2026-27 में 65 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को सशक्त करने के लिए सहकारिता के माध्यम से ठोस कदम उठाए गए हैं। पहले किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता था, जिससे किसानों पर बोझ पड़ता था और बैंक भी घाटे में थे, क्योंकि उनका पैसा डूब जाता था। हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लघु र सीमांत किसानों को 5 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, शेष सहयोग सरकार करेगी। जब किसानों को आसान ब्याज दर और सरल किस्तों पर ऋण मिलेगा तो वे खेती में निवेश करेंगे, तकनीक अपनाएंगे और उनकी आय में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी।

अनलिमिटेड पोटेंशियल को साकार कर रहा यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश ही नहीं, दुनिया का पहला राज्य है, जहां 86 प्रतिशत भूमि सिंचित है। 16 लाख ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली दी जा रही है, नहरों से सिंचाई मुफ्त है और एक लाख किसानों को सोलर पैनल दिए जा चुके हैं। एक समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला राज्य बन चुका है। 10 वर्ष पहले देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान मात्र 8 प्रतिशत था, जबकि आज यह बढ़कर 9.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपये की थी, जो इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। यह परिवर्तन अपने आप में एक बड़ा ब्रेकथ्रू है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल रेवेन्यू सरप्लस स्टेट ही नहीं है, बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण बन चुका है। 2016 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 43 हजार थी, जो आज बढ़कर 1.20 लाख हो चुकी है। हमारा फिस्कल डेफिसिट 3 प्रतिशत से भी कम है। कई वर्षों से प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। देश में डीजल-पेट्रोल सबसे कम दाम पर यूपी में मिलता है। कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत से अधिक हो गई है। देश की आबदी का 17 प्रतिशत हिस्सा यूपी में निवास करता है, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 11 प्रतिशत है। इसके बावजूद हमारा अन्नदाता किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21 फीसदी उत्पादन कर रहा है। एथेनॉल व चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक है। वर्ष 2000 से 2017 के बीच यानी 17 सालों में प्रदेश के गन्ना किसानों को मात्र 2 लाख 14 हजार करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि हमने पिछले नौ वर्षों में ही किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है, यानी 86 हजार करोड़ ज्यादा। आज यूपी नंबर 8 से उठकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है।

ऋण वितरण शर्तों को सरल बनाएं बैंक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकरों से अपील करते हुए कहा कि वे ऋण वितरण में शर्तों को यथासंभव सरल करें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसानों, एफपीओ, एमएसएमई और सहकारिता से जुड़े लोगों को सहयोग दें। सिर्फ नीति बनाना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि छोटे-छोटे समूह बनाकर लक्षित प्रशिक्षण दिया जाए, मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएं और उन्हें सीधे उन लोगों के बीच भेजा जाए, जो एफपीओ, एमएसएमई, सर्विस सेक्टर, लखपति दीदी के लिए प्रस्तावित शी-मार्ट मॉडल या सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक, नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थान अगर ट्रेनिंग और क्रेडिट को साथ लेकर चलें, तो प्रदेश में रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है। तकनीक, ट्रेनिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए उत्तर प्रदेश अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को साकार कर रहा है और यही प्रयास प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नाबार्ड के महाप्रबंधक पंकज कुमार और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक पंकज कुमार उपस्थित रहे।

यूपी की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में होगी 'मॉम-2' की शूटिंग

सेट के लिए शुरू हुई लैंड मैपिंग, 20 दिन में तैयार होगा शूटिंग सेट

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'इंटरनेशनल फिल्म सिटी' ने अब जमीनी रफ्तार पकड़ ली है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में विकसित की जा रही उत्तर प्रदेश की इस पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में पहली फिल्म शूटिंग के रूप में 'मॉम-2' का फिल्मांकन होने जा रहा है। फिल्म सिटी परिसर में शूटिंग को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परियोजना का निर्माण कर रहे बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर 'बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड' ने जमीन की मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मैपिंग पूरी होने के बाद करीब 20 दिनों के भीतर शूटिंग सेट तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का कार्य बॉलीवुड के प्रसिद्ध निमार्ता-निर्देशक बोनी कपूर व भूटानी ग्रुप को संयुक्त रूप से मिला है। इस कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यीडा द्वारा लेआउट प्लान को मंजूरी दिए जाने के बाद परियोजना के पहले चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के जीएम राजीव अरोड़ा ने बताया कि शूटिंग की तैयारियों के साथ-साथ फिल्म सिटी के निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जमीन की मैपिंग पूरी होने के बाद करीब 20 दिनों के भीतर शूटिंग सेट तैयार कर लिया जाएगा, जिससे फिल्म निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। इसके साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही सीएम योगी व पीएम मोदी के कर कमलों से इसका विधिवत शुभारंभ होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बोनी कपूर की कंपनी ने ही 2017 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'मॉम' को प्रोड्यूस किया था और अब उन्होंने इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग को यूपी में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-21 में विकसित की जा रही है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फिल्म, ओटीटी, वेब सीरीज समेत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट विकसित हो रही यह फिल्म सिटी आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ प्रदेश को एक एंटरटेनमेंट और एविएशन हब के रूप में स्थापित करेगी।

डीडीआरडब्लयूए फेडरेशन ने सीईओ से की मुलाकात, उठाई 6 प्रमुख समस्या

आपदा के वक्त हैलीकॉप्टर का उपयोग किया जाए : ठा. एनपी सिंह

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

नोएडा। डीडीआरडब्लयूए फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करूणेश से मुलाकात कर 6 बिन्दुओं पर उनसे चर्चा की। सेक्टर-150 के हादसे के बाद लोगों के जान माल की रक्षा के लिए डीडीआरडब्ल्यूए ने सीईओ को दो पत्र भी प्रेषित किए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया गया कि दोनों पत्र के सभी बिंदुओं पर प्राधिकरण द्वारा तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। क्यूआरटी टीम गठित करने पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी वर्क सर्कल को आदेशित किया गया है कि वह अपने एरिया की आरडब्लूए से नियमित हर महीने मीटिंग करेंगे और उसकी मिनिट्स आफ मीटिंग बनाकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ऑफिस में सबमिट करेंगे और आरडब्लूए को भी उपलब्ध करवाएंगे। गलत यू टर्न और रोड इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने हेतु एक टीम का गठन किया जाएगा और नोएडा शहर की आरडब्लूए और फेडरेशन को भी सम्मिलित किया जाएगा। नालो को कवर करने हेतु सभी वर्क सर्कल को आदेशित कर दिया गया है और वह इस पर कार्य कर रहे हैं जो भी आरडब्लूए इसमें सहयोग करेगी और राय देगी उस पर कार्य किया जाएगा। हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने पर प्रशासन शासन और अपनी टीम से चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रिकल बसो के मुद्दे पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया की 20 बसे 15 दिनों के अंदर ही शुरूआत करवाने पर मंथन किया जाएगा यह एक अत्यधिक आवश्यक पॉइंट है जिस पर प्राधिकरण को कार्य करने की आवश्यकता है। सिटिजन चार्टर पर जोर दिया जाएगा। शहर में ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा और डीडीआरडब्ल्यू फेडरेशन से लगातार मीटिंग करके सुझाव देनी हेतु अनुरोध किया गया और ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट पर फेडरेशन की सलाह मांगी गई। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी तुरंत कार्रवाई करने हेतु आश्वासन दिया गया अन्य सभी बिंदुओं पर भी तुरंत काम करने हेतु आश्वासन दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष एन पी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अनिल खन्ना और अनिल सिंह, सेक्रेटरी प्रमोद वर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष महिपाल चौहान, लीगल एडवाइजर अनीता पांडेय, सौरव जैन व अन्य लोग मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की 'एकला चलो' नीति, लेफ्ट से टूटा एलियांस, सभी 294 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनावों पर कांग्रेस की बैठक के बाद बोलते हुए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आज एक बैठक हुई और उसमें सभी उपस्थित थे। विषय था पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के बारे में पार्टी नेताओं के विचार, आगे की रणनीति। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। सभी के विचार सुने गए। नेतृत्व का मत था कि इस बार हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे।

मीर ने आगे जोर देते हुए कहा कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले को राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है, और कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में, हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम राज्य की 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के साथ खड़ा है। कांग्रेस का यह कदम पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच आया है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है।

इसी बीच, भाजपा चुनाव की तैयारियों को मजबूत कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ एक रणनीतिक बैठक की, जिसमें संगठनात्मक मामलों और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद, भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि नितिन नबीन ने सांसदों को मार्गदर्शन दिया और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। राजू बिस्टा ने पत्रकारों से कहा कि पश्चिम बंगाल के हमारे सभी सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और नवनिर्वाचित सांसद भी।

हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दो घंटे से अधिक समय बिताने और अपनी चिंताओं पर चर्चा करने का अवसर मिला। यह पूरी तरह से एक संगठनात्मक बैठक थी, और उनसे हमारी यह पहली मुलाकात थी, इसलिए हमें कई सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए। यही कारण है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग मानता हूं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पारिवारिक माहौल में मुलाकात की, और सभी सांसदों ने अपनी-अपनी

यूपी में 06 से 13 फरवरी तक चलेगा 'दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0'

योगी सरकार का दिव्यांगजनों के सेवायोजन के साथ स्व-रोजगार पर भी फोकस, सभी जनपदों में चलेगा एक सप्ताह का विशेष अभियान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और ठोस पहल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में 06 से 13 फरवरी 2026 तक ह्लदिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0ह्व संचालित किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सेवायोजन के साथ-साथ स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योगी सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक आजीविका, आत्मनिर्भरता और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।

तीन वर्षों में प्रशिक्षित दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत विगत तीन वर्षों में कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित ऐसे पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जो वर्तमान में जनपदों में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जनपद स्तर पर उपलब्ध अन्य इच्छुक दिव्यांगजन भी इस अभियान का लाभ ले सकेंगे।

औद्योगिक इकाइयों में सेवायोजन पर जोर

दिव्यांगजन रोजगार अभियान के दौरान जनपदों में संचालित औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य अधिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजनों का सेवायोजन कराया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र तथा अन्य विभागों की स्व-रोजगार योजनाओं से भी दिव्यांगजनों को जोड़ा जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालन

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि हर जनपद में यह अभियान मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला रोजगार सहायता अधिकारी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक शामिल होंगे। निर्धारित अवधि में राजकीय आईटीआई को केंद्र बनाकर सेवायोजन एवं स्व-रोजगार संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

रोजगार संगम पोर्टल से भी मिलेगा अवसर

रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत इच्छुक दिव्यांगजनों को भी इस अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध रिक्तियों पर नियोजित कराया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि अभियान का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इस अवसर का लाभ उठा सकें और रोजगार की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

टॉप-5 जनपदों को मिलेगा सम्मान

अभियान के सफल क्रियान्वयन पर सर्वाधिक सेवायोजन एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के शीर्ष 05 जनपदों के जिलाधिकारियों एवं उनकी टीम को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। 13 फरवरी 2026 को सायं 5 बजे तक सभी जनपदों से सेवायोजित दिव्यांगजनों की संख्या, नियुक्ति पत्र एवं स्व-रोजगार से जुड़े साक्ष्य मांगे जाएंगे।